निवेशकों की प्रस्तुति और प्रदर्शन की मुख्य बातें तीसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026

हुडको
hudco
A NAVRATNA CPSE
विकसित भारत
के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर
वित्तपोषण

hudco
UiWIN
URBAN INVEST WINDOW

@hudcolimited facebook.com/hudco youtube.com@HUDCOLTD linkedin.com/hudco-limited

विषय-सूची

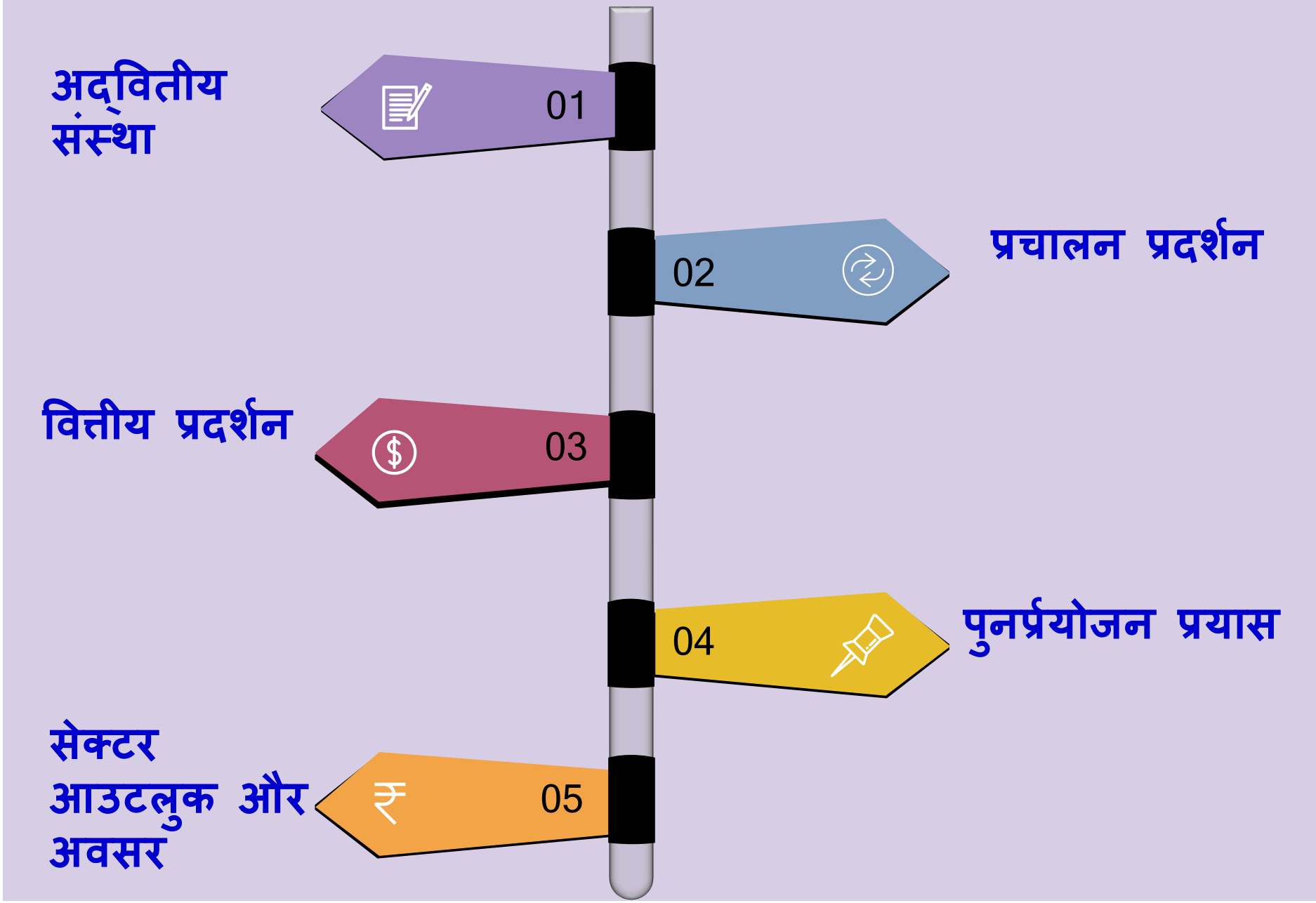
अद्वितीय संस्था
01
प्रचालन प्रदर्शन
02
वित्तीय प्रदर्शन
03
पुनर्प्रयोजन प्रयास
04
सेक्टर आउटलुक और अवसर
05

हडको - अद्वितीय संस्था

- टेक्नो-फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में 5 दशक से ज़्यादा का अनुभव।
- वित्तपोषण, परामर्श प्रदान करने वाला एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और क्षमता निर्माण समर्थन– आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के संपूर्ण परिदृश्य।
- राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ सघन संबंधों के साथ मल्टी सेक्टरल फोकस।
- भारत सरकार के प्रयासों में मदद करने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर – पीएमईवाई 2.0 , स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, आदि।
- भारत सरकार की 75% ओनरशिप वाली लिस्टेड कंपनी।
- एक नवरत्न सीपीएसई जो रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ एनबीएफसी-आईएफसी के रूप में पंजीकृत' है।
- निरंतर लाभ आर्जित करने वाली कंपनी जिसका मोटो है "प्रोफिटेबिलिटी विद सोशल जस्टिस"

प्रमुख उपलब्धियाँ: एचएफसी से आईएफसी तक

1970-80: स्थापना और अग्रणी

- 1970: विकास संस्थान के रूप में निगमित
- भारत में घरों की कमी को दूर करने के लिए

1980-90: विविधीकरण

- 1985: एचएसएमआई
- 1989: अर्बन इन्फ्रा विंडो

1990-00: उन्नत अधिदेश- सरकारी मान्यता

- 2MHP में अहम भूमिका
- शीर्ष 10 PSUs को पीएम अवॉर्ड

2000-10: मिनीरत्न मान्यता

- प्राधिकरण पूंजी- ₹2,500 करोड़
- 2002: अनुसूची-ए
- 2004: मिनीरत्न-I

2010-20: बेहतर बाजार स्थिति

- क्रेडिट रेटिंग : "AAA"
- पब्लिक इशू: टैक्स फ्री बॉन्ड
- आईपीओ

पोस्ट 2020: सफलता और धन सृजन

- नवरत्न और एनबीएफसी आईएफसी
- घातीय वृद्धि
- SHs में भारी वापसी
- 54 ईसी बांड और जेडसीबी

2025: हडको का पुन: प्रयोजन

- (UiWIN) का शुभारंभ

लगातार दूसरे वर्ष (वित्त वर्ष24 और वित्त वर्ष25) "एक्सीलेंट" एमओयू रेटिंग

- अपने कई प्रतिद्वंदियों से आगे
- लगातार प्रचालन और वित्तीय उत्कृष्टता

पैन-इंडिया उपस्थिति

- कॉर्पोरेट / रजिस्टर्ड ऑफिस : नई दिल्ली
- 20 क्षेत्रीय कार्यालयों और 11 विकास कार्यालयों के माध्यम से बहुक्षेत्रीय फोकस
- ट्रेनिंग और रिसर्च आर्म - ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (HSMI), नई दिल्ली
- कार्मिकों की संख्या (दिसंबर, 2025 तक)- 581

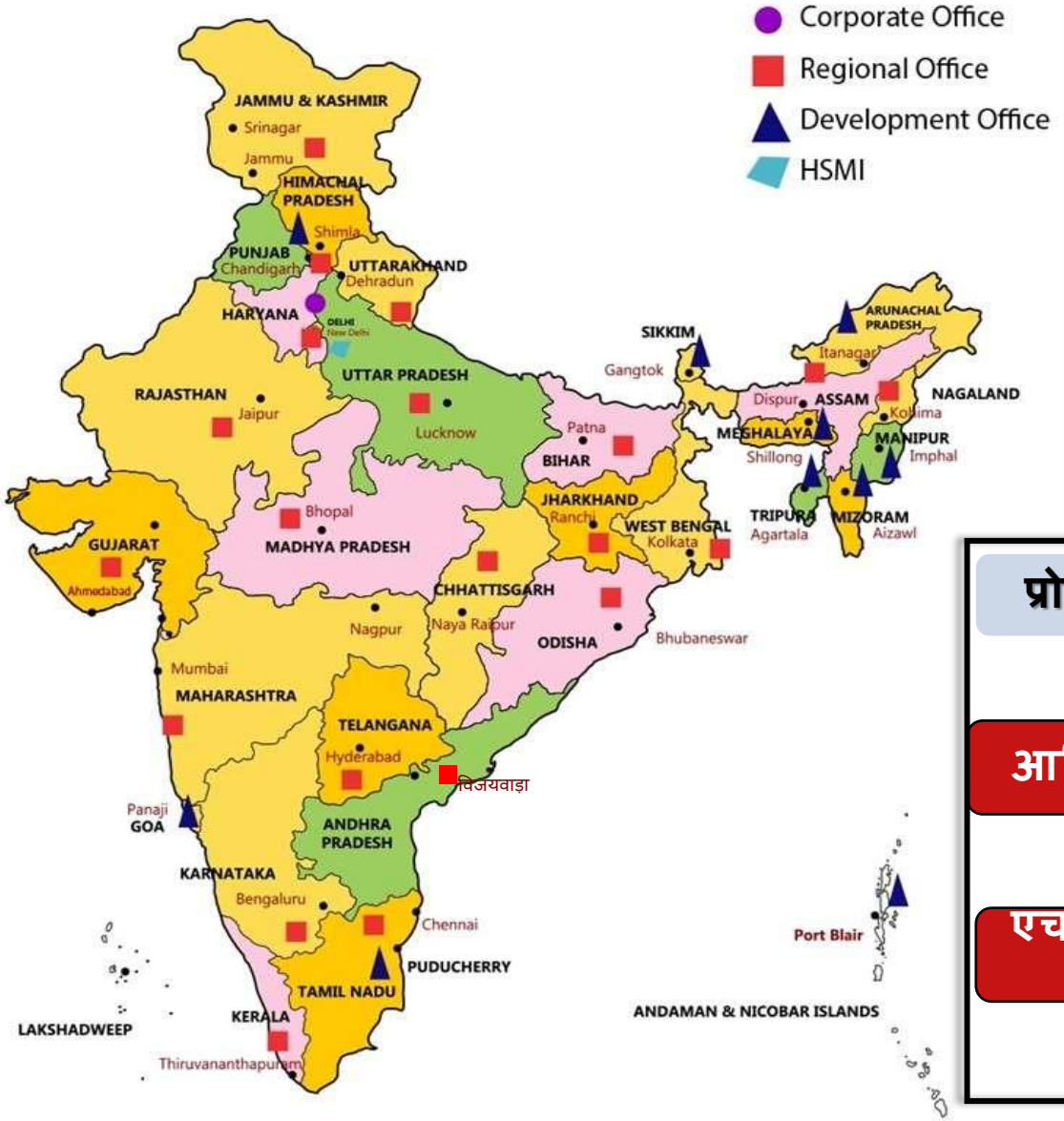

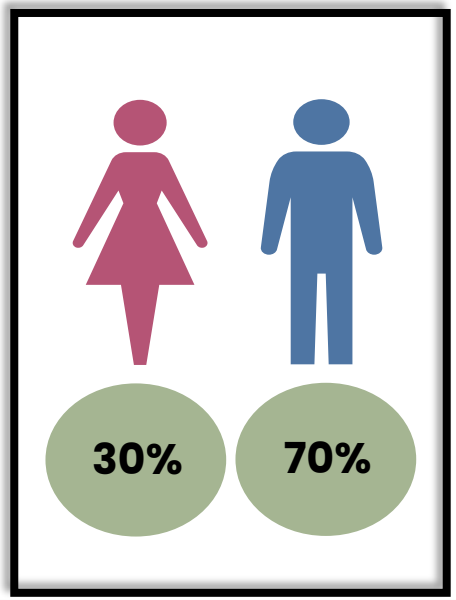

प्रोफेशनल्स का विविध समूह

- वित्त
- आर्किटेक्ट्स
- इंजीनियर
- अर्थशास्त्री
- एचआर और आईटी
- विधिक
- नगर नियोजक

(सक्षम करना - बिज़नेस डायवर्सिफिकेशन, बेहतर ब्रांड पहचान, राज्य सरकारों के साथ मजबूत पार्टनरशिप और इन्वेस्टर आउटरीच)

प्रमुख शक्तियां

- पैन-इंडियाउपस्थिति
- राज्यों के साथ मजबूत संबंध

मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता
- सबसे कम एनपीए
- उच्च प्रोव. कवरेज अनुपात

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग:
- घरेलू-एएए
- अंतर्राष्ट्रीय-संप्रभु

सरकार के कार्यक्रम/मिशन में मुख्य भूमिका

- मजबूत वित्तीय अनुपात
- निरंतर लाभप्रदता

वन स्टॉप सॉल्यूशन:
- फाइनेंसिंग
- कंसल्टेंसी
- क्षमता निर्माण

360° सतत संपत्ति निर्माण के लिए साझेदारी

वित्तपोषण

- किफायती आवास
- इंफ्रास्ट्रक्चर :
  - सामाजिक इन्फ्रा - अस्पताल, सरकार भवन , जल आपूर्ति ;
  - वाणिज्यिक इन्फ्रा - सड़क, राजमार्ग, शहरी गतिशीलता, बंदरगाह, ऊर्जा
- भूमि अधिग्रहण

भारत सरकार की योजनाएँ

समकक्ष अनुदान

- पीएमएवाई- शहरी और ग्रामीण
- स्मार्ट सिटी
- अमृत
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल जीवन मिशन

कंसल्टेंसी

- वास्तु
- शहरी और क्षेत्रीय योजना
- मूल्यांकन और निगरानी
- संपत्ति मुद्रीकरण
- पर्यावरण अध्ययन

क्षमता निर्माण

- प्रोफेशनल्स का प्रशिक्षण / इन-हाउस कार्मिक
- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोग्राम
- शहरी क्षेत्रों में अनुसंधान समर्थन ।

उधार लेने वाले भागीदार: केंद्र/राज्य सरकार, राज्य की सार्वजनिक एजेंसियां, यूएलबी और विशेष संस्थाएं

हडको में ईएसजी – एक सतत भविष्य का निर्माण

- सस्टेनेबल लेंडिंग* :
  - ➢ ₹ 19,931 करोड़ - आरई और नेट जीरो
  - ➢ ₹ 23,664 करोड़ - स्वच्छता, सीवरेज आदि।
- प्रचालन का कम पर्यावरणीय प्रभाव
- पेपरलेस में बदलाव
- ऑफिस फ्लीट : धीरे-धीरे EV

- प्रभावशाली सीएसआर - ₹ 52.72 करोड़ (वित्त वर्ष25)
- ईडब्ल्यूएस और अफोर्डेबल हाउसिंग* - ₹ 11,051 करोड़
- कार्यस्थल सुरक्षा और शिकायत निवारण
- पर्याप्त खरीद - एमएसएमई
- 44 सीटीयू को अपनाया गया: स्वच्छता ही सेवा

- स्वतंत्र और हेल्दी बोर्ड
- बोर्ड डायवर्सिटी (महिलाएं): 12.5%
- अनुभवी नेतृत्व
- 66.44% कर्मचारी प्रशिक्षण कवरेज
- हितधारक जुड़ाव
- पारदर्शी और आईटी संचालित प्रचालन

ईएसजी रेटिंग	SUSTAINALYTICS	18.2(कम जोखिम)	Crisil ESG Ratings & Analytics	58 (पर्याप्त)	NSE Sustainability Ratings & Analytics	50 (स्टेबल)

ईएसजी रिपोर्ट 2024-25

*01.01.24 से अब तक

उच्चतम क्रेडिट रेटिंग (कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉन्ड सहित)

घरेलू - एएए

India Ratings & Research
इंड एएए (स्टेबल)

ICRA
एएए (स्टेबल)

CARE Ratings
एएए (स्टेबल)

अंतर्राष्ट्रीय - संप्रभु

JCR
Japan Credit Rating Agency, Ltd.
बीबीबी+ (स्टेबल)

Fitch Ratings
बीबीबी- (स्टेबल)

Moody's
बीएए3 (स्टेबल)

- स्ट्रांगर लेंडिंग क्षमता
- उधारकर्ताओं द्वारा विश्वसनीय

- वैश्विक वित्तीय विश्वसनीयता
- कम-जोखिम प्रोफ़ाइल

31-दिसंबर-2025 तक शेयरहोल्डर्स की संभावना

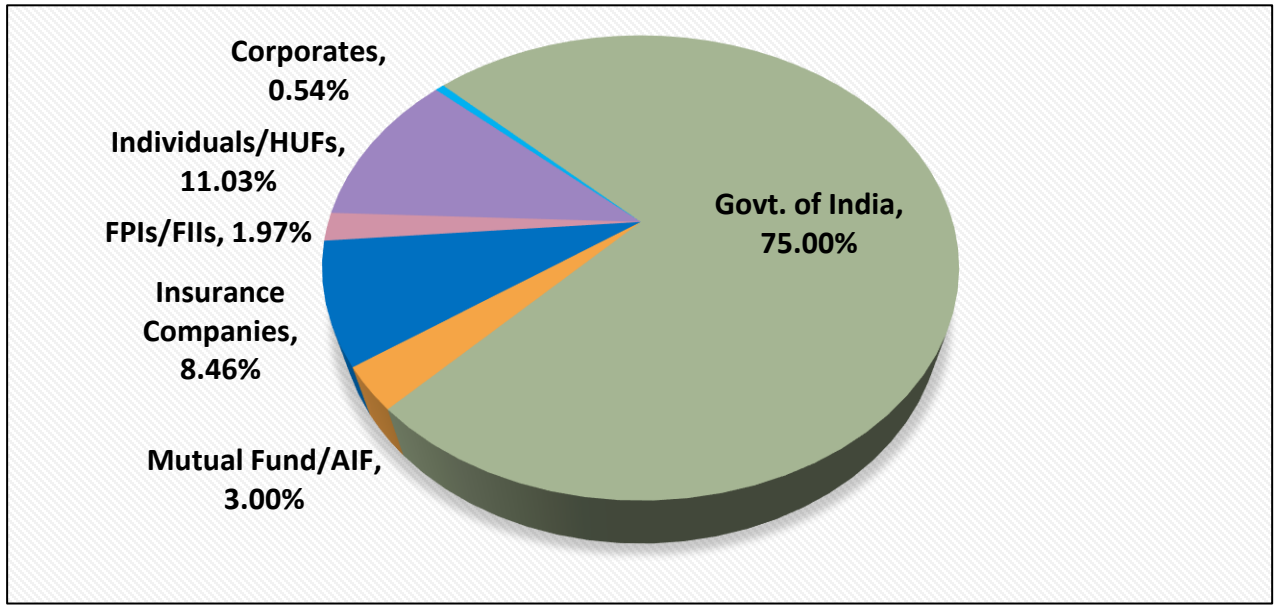

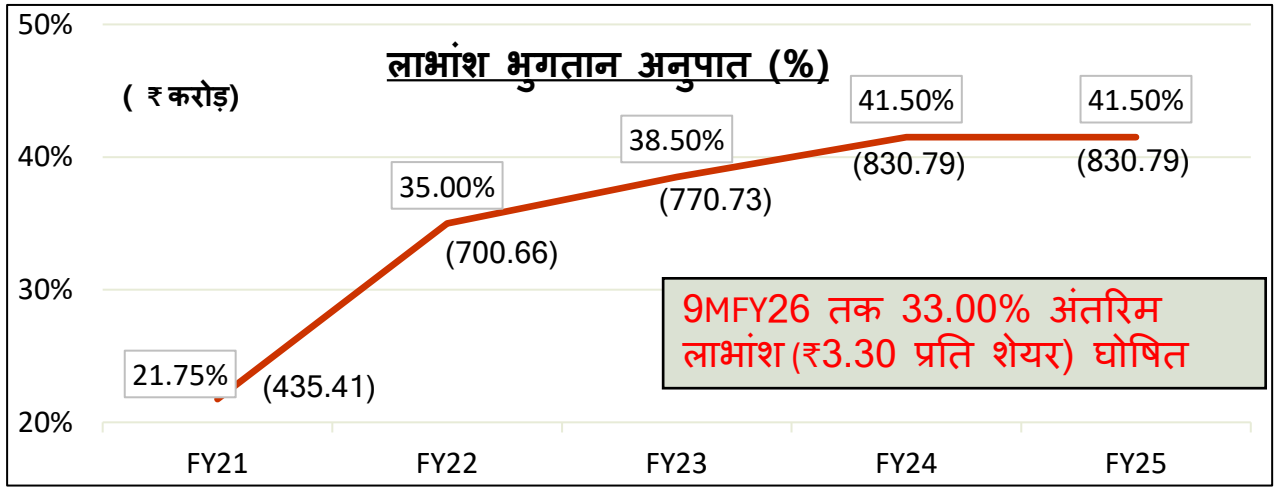

शीर्ष 10 शेयरहोल्डर्स

नाम	शेयरहोल्डिंग %
भारत सरकार	75.00
एलआईसी ऑफ इंडिया	7.39
एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड	0.81
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.73
आदित्य बिड़ला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	0.42
वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	0.37
वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड	0.34
सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	0.27
बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड	0 .23
एमकेटी कैपिटल एल.पी.	0.20

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और निवेशकों के भरोसे में वृद्धि

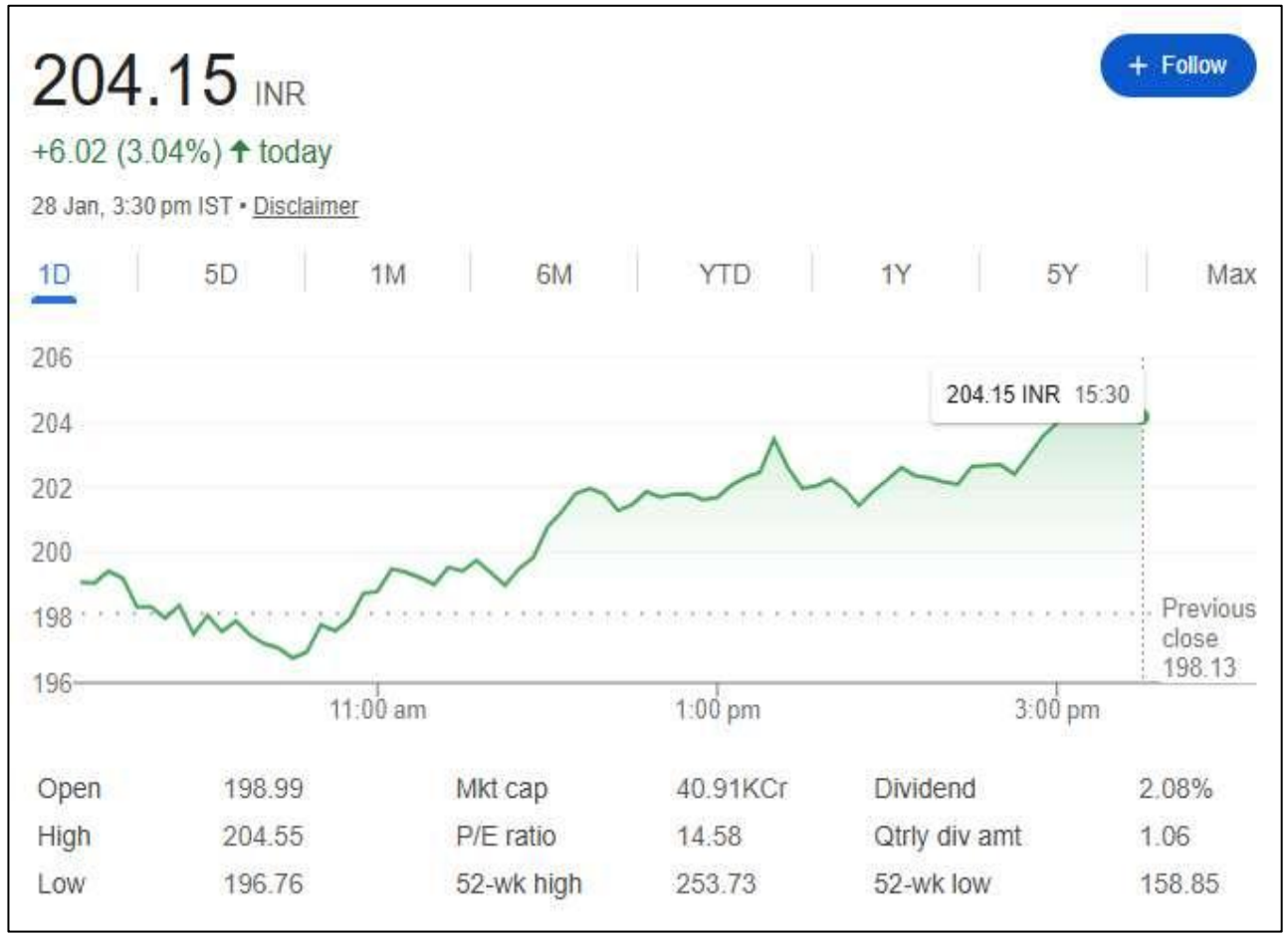

(₹ करोड़)

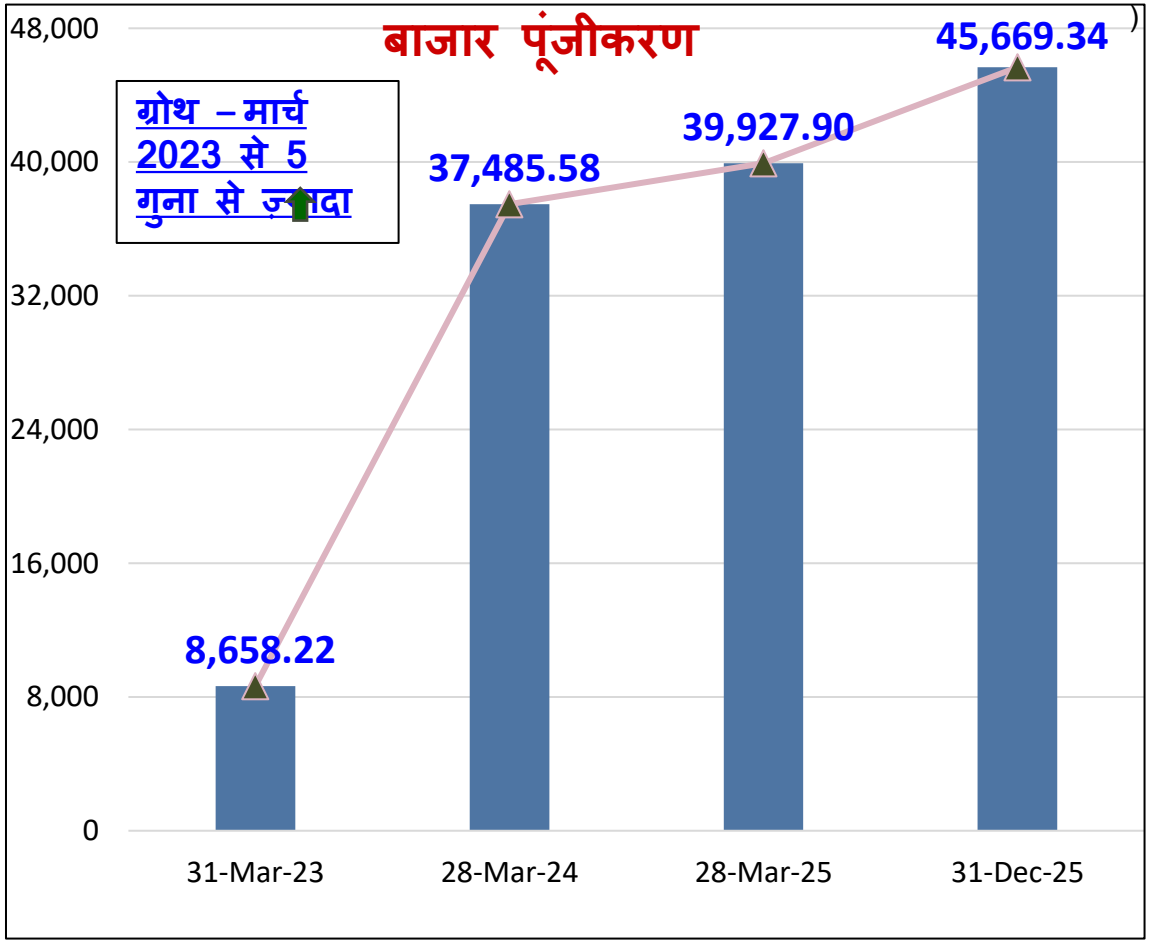

- मार्केट कैप के अनुसार टॉप 200 कंपनियों में
- हडको के शेयर डेरिवेटिव मार्केट में भी ट्रेड हुए

प्रति शेयर आय ₹ 13.67 (वार्षिक)

प्रति शेयर बुक वैल्यू ₹ 93.64

प्रचालन प्रदर्शन

विकास प्रक्षेप पथ

ऋण पोर्टफोलियो

श्रेणीवार स्वीकृतियां

श्रेणीवार संवितरण

अद्वितीय प्रक्षेप पथ

ऋण स्वीकृतियां (करोड़ रुपये में)

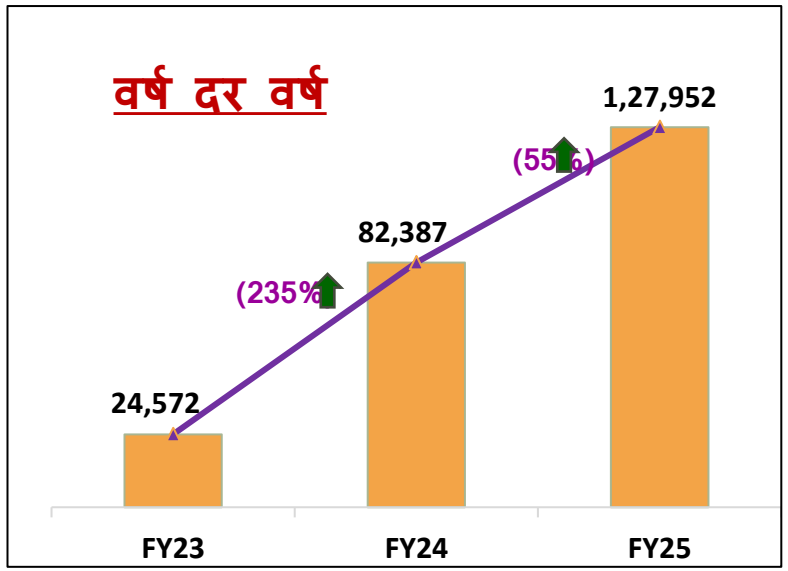

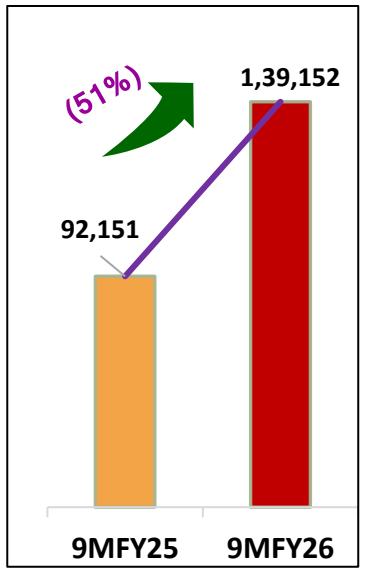

ऋण संवितरण (करोड़ रुपये में)

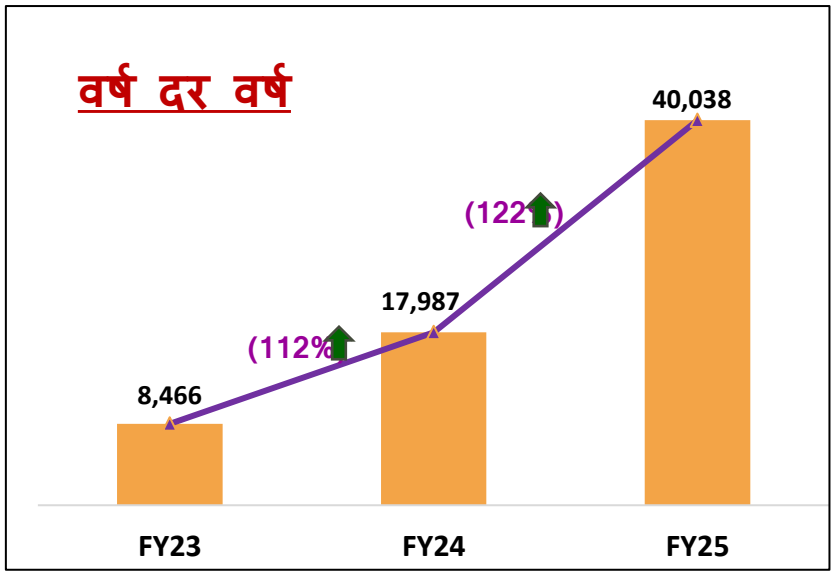

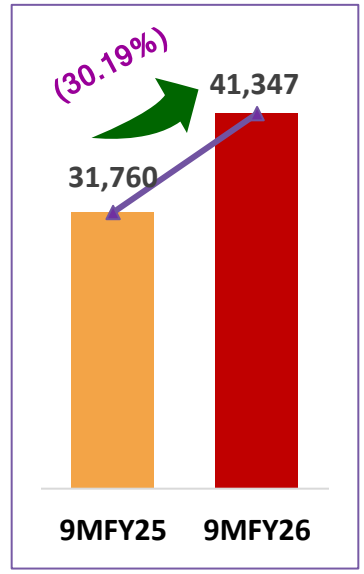

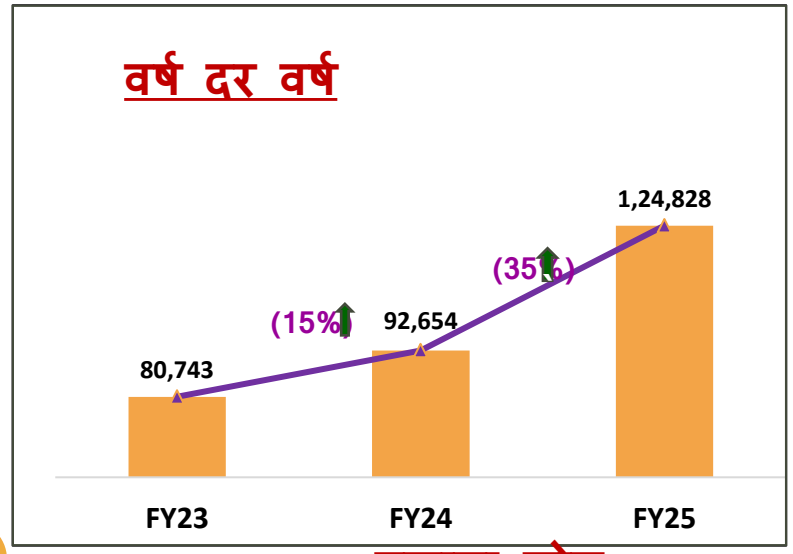

बकाया लोन (करोड़ रुपये में)

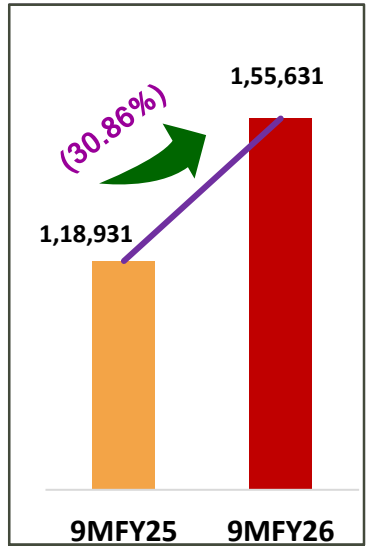

ब्याज आय (करोड़ रुपये में)

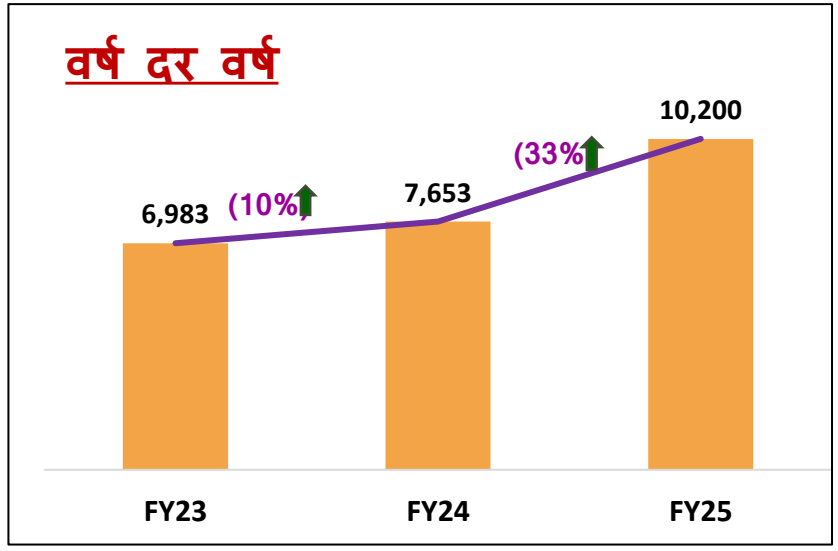

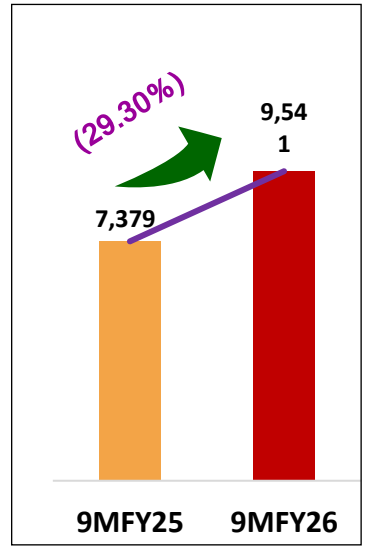

ऋण पोर्टफोलियो

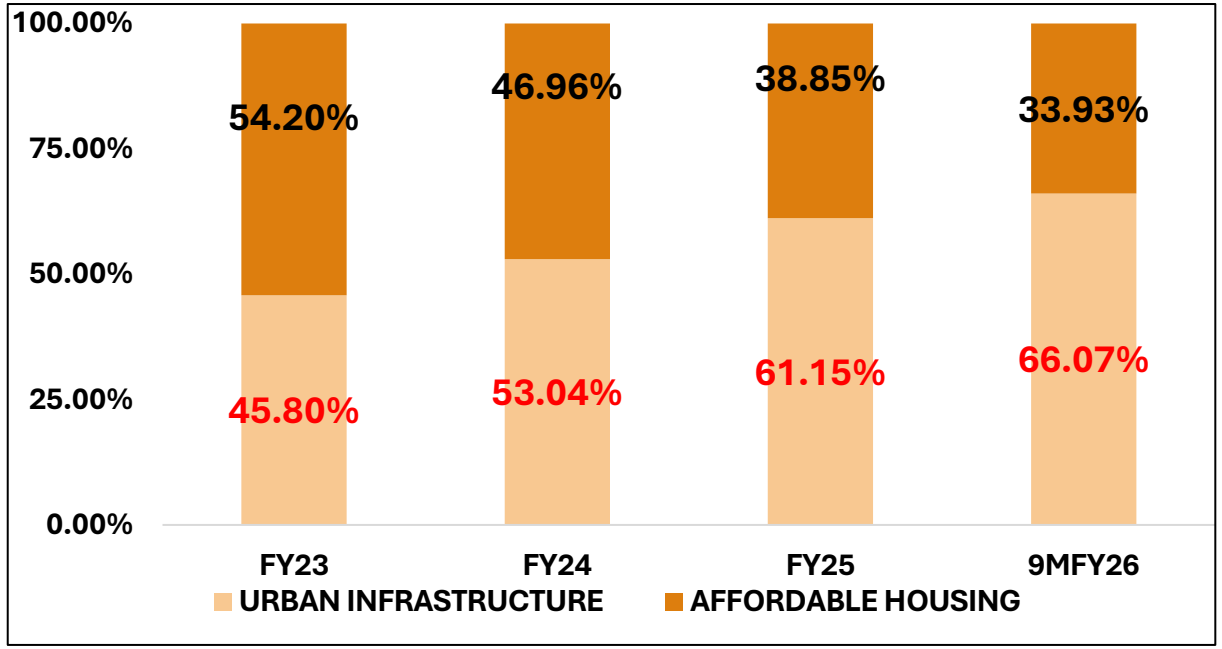

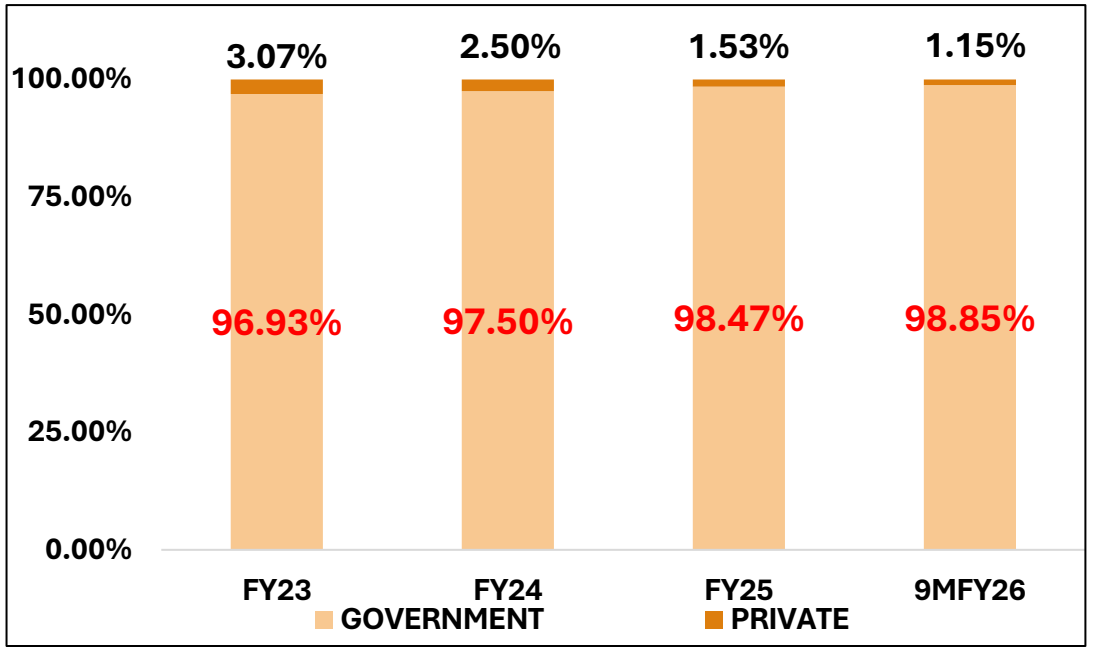

विवरण (करोड़ रुपये में)	वित्त वर्ष 23	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	नौ माह	
				वित्त वर्ष 26	वित्त वर्ष 25
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर	36,982	49,143	76,333	1,02,827	71,153
किफायती आवास	43,761	43,511	48,495	52,804	47,778
कुल	80,743	92,654	1,24,828	1,55,631	1,18,931
सरकार	78,267	90,342	1,22,920	1,53,835	1,16,914
निजी	2,476	2,312	1,908	1,796	2,017

वित्तीय प्रदर्शन पर एक नज़र

- बोर्रोविंग प्रोफाइल
- परिसंपत्ति की गुणवत्ता
- मुख्य वित्तीय मुख्य बिंदु

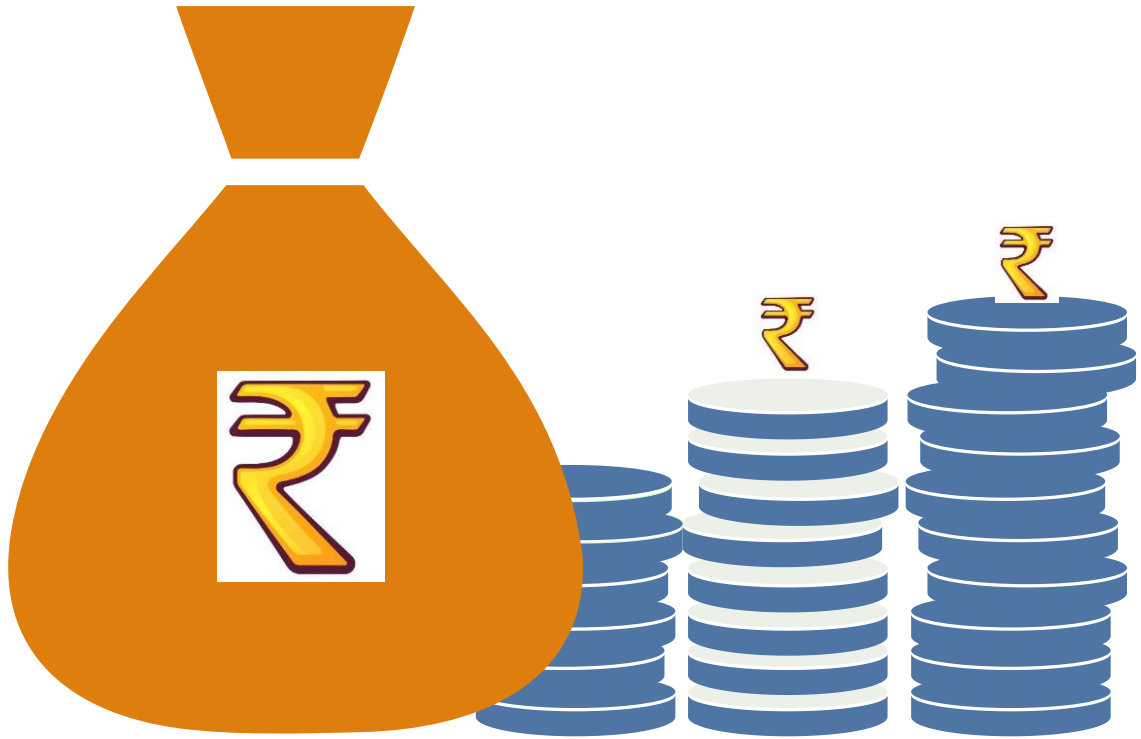

बेहतर लायबिलिटी मैनेजमेंट – मार्जिन में बढ़ोतरी

(₹ करोड़ में)

वर्ग	नौमाह				वार्षिक			
	वित्त वर्ष 26	औसत लागत	वित्त वर्ष 25	औसत लागत	वित्त वर्ष 25	औसत लागत	वित्त वर्ष 24	औसत लागत
कर योग्य बांड	10,331.39	6.80%	7,016.00	7.27 %	14,768.50	7.28%	1,500.00	7.48%
बैंक / एफआई ऋण								
- लघु अवधि	3,888.76	5.77%	7,897.20	7.14%	4,555.68	7.21%	6,654.56	7.32%
- मध्यम अवधि	36,665.87	6.30%	9,938.00	7.61%	10,067.00	7.47%	9,002.50	7.55%
- एफसीएनआर(बी)	-	-	9,720.97	5.96%	15,563.34	6.06%	3,990.18	5.96%
विदेशी मुद्रा	2,974.20	5.98%	4,471.37	5.51%	6,178.87	5.70%	827.85	5.29%
कुल	53,860.22	6.34%	39,043.54	6.80%	51,133.39	6.75%	21,975.13	7.10%

वित्त वर्ष26 की नौ माह में ₹53,860.22 करोड़ जुटाए गए , जबकि पिछले वित्त वर्ष25 की नौ माह में ₹39,043.54 करोड़ था।

बोर्रोविंग प्रोफ़ाइल

(₹ करोड़ में)

विवरण	9माह-वित्त वर्ष 2026	9माह-वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष25	वित्त वर्ष24
क. भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड	20,000.00	20,000	20,000.00	20,000.00
ख. अन्य				
कर मुक्त बांड	11,083.88	12,372.38	12,372.38	12,372.38
कर योग्य बांड*	31,609.89	16,826.00	23,578.50	9,810.00
बैंक ऋण				
- लघु अवधि	3,888.69	7,897.20	4,555.68	6,654.56
- मध्यावधि	49,770.61	22,725.81	23,854.78	19,756.55
विदेशी मुद्रा ऋण				
- एफसीएनआर(बी)	5,842.37	12,212.83	15,563.34	3,990.18
- ईसीबी/ओडीए	10,034.59	5,361.49	7,063.59	8 94.03
एनएचबी/अन्य एफआई से पुनर्वित्त सहायता	4,185.37	3,411.37	292.33	554.52
उप-योग (बी)	**1,16,415.40**	**80,807.08**	**87,280.60**	**54,032.22**

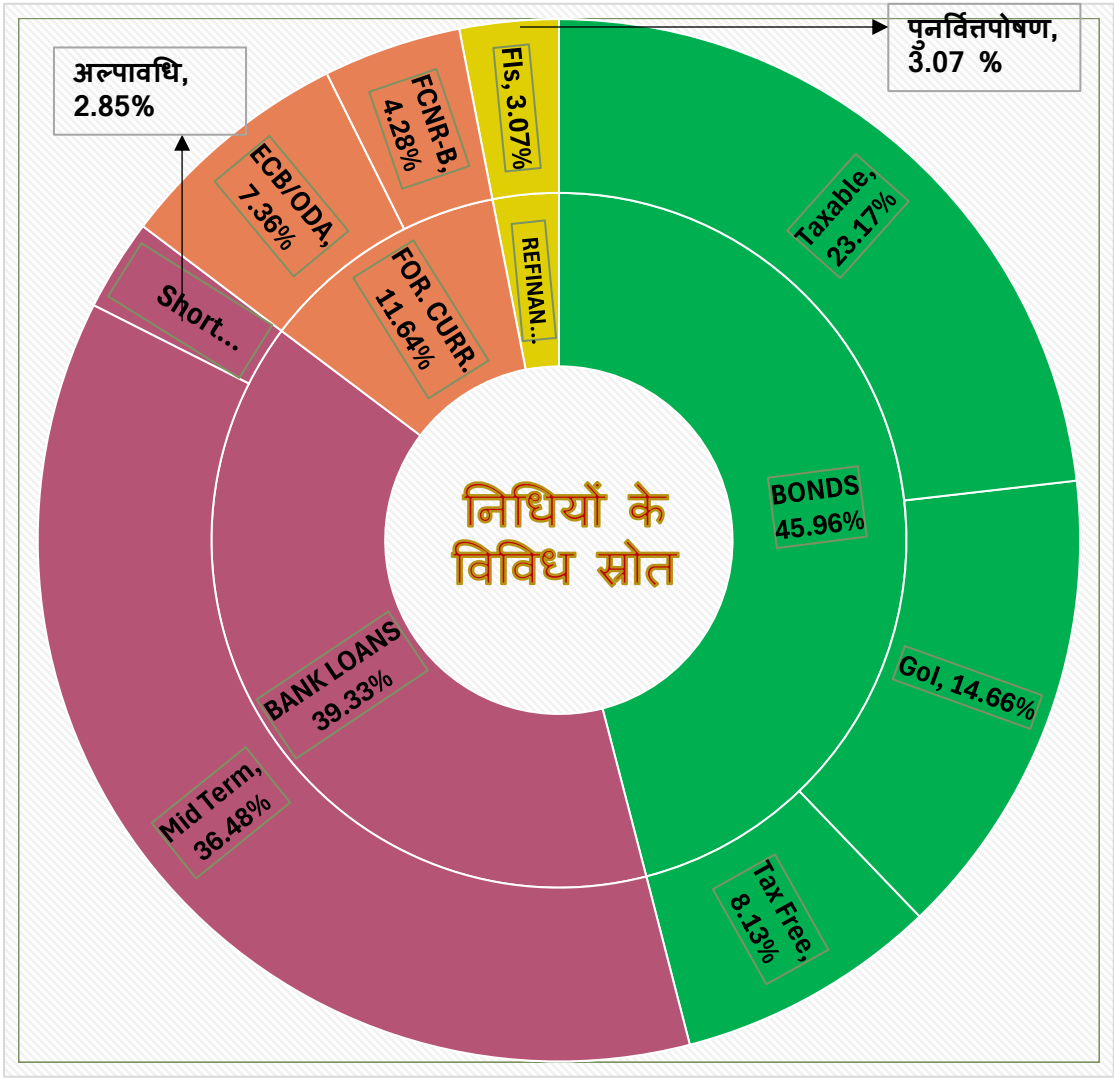

बिज़नेस ग्रोथ को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सोर्स से फंडिंग के कई सोर्स तक एक्सेस।

लागत अनुकूलन के प्रयास

- ALM प्रोफ़ाइल के आधार पर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दोनों तरह के अलग-अलग सोर्स से **लिए गए उधार का सही मिक्स ।**
- मौजूदा कम ब्याज दर वाले सिस्टम का फ़ायदा उठाने के लिए **घरेलू उधार में स्ट्रेटेजिक बढ़ोतरी ।**
- **अंतर्राष्ट्रीय फुटप्रिंट्स को मजबूत करना**
  - 5 साल के लिए 70 बिलियन (₹ 4,000 करोड़) का **नया** उधार ।
  - USD / EURO / YEN लोन/बॉन्ड जुटाने की संभावना सहित, **अलग-अलग जगहों पर** खोज करना ।
  - पहली बॉन्ड पेशकश के ज़रिए इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से फंड जुटाने के लिए जीएमटीएन प्रोग्राम को सेट करना
- **बहुपक्षीय वित्तपोषण** साझेदारी – केएफडब्ल्यू के साथ ऋण को अंतिम रूप दिया गया तथा एआईआईबी, विश्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है।
- सही लेवल पर हेज/प्रोटेक्शन के साथ करेंसी रिस्क से निपटने के लिए **इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को** मज़बूत करना
- **54EC कैपिटल गेन बॉन्ड के ज़रिए फंड जुटाना**

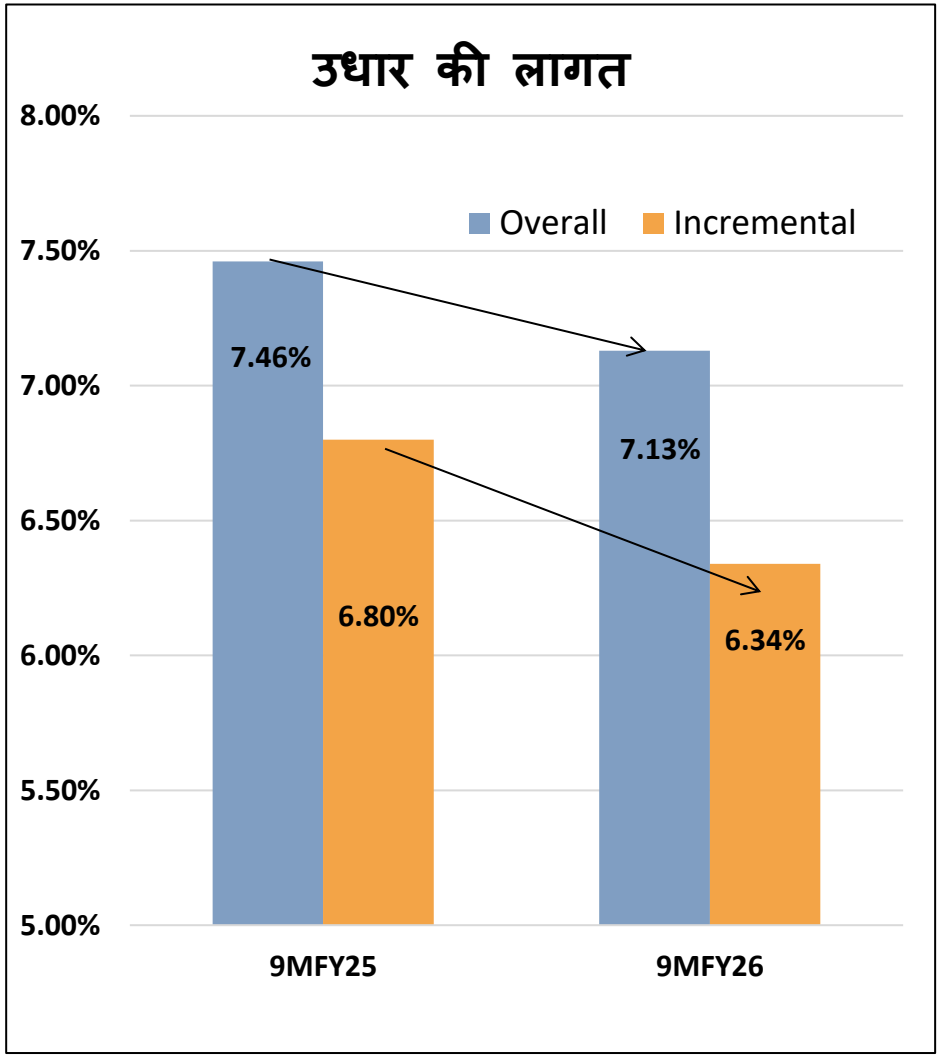

बेहतरीन परिसंपत्ति गुणवत्ता – एक कॉम्पिटिटिव बढ़त

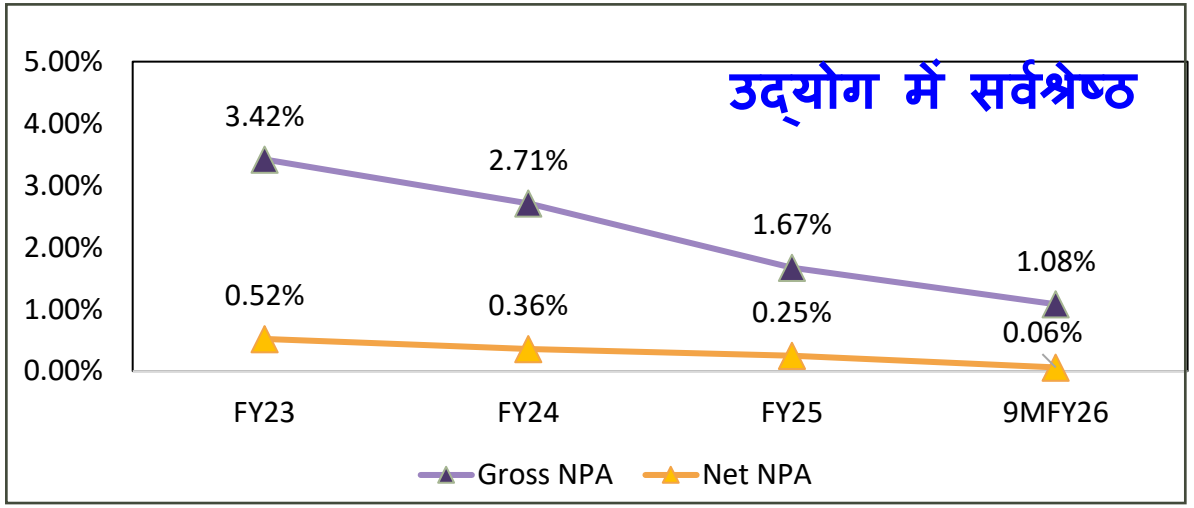

पर्याप्त प्रावधान कवरेज अनुपात (%) [1]

1. प्रोविज़न कवरेज रेश्यो NPA लोन के खिलाफ़ बनाए गए प्रोविज़न के रेश्यो को दिखाता है

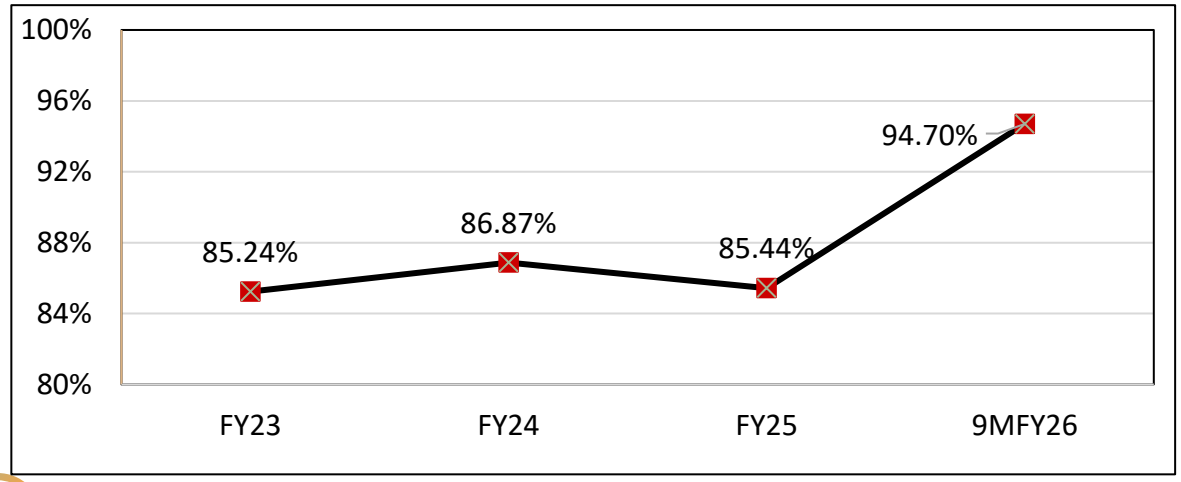

- **मजबूत मूल्यांकन और निगरानी मैकेनिज्म**
- **नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा** - सर्वोत्तम बाजार प्रैक्टिसेस के अनुरूप
- **सरकार और उसकी एजेंसियों को लोन** : लोन बुक का 98.85% हिस्सा सरकार और उसकी एजेंसियों को दिए गए लोन का है।
- **सरकारी गारंटी वाले लोन** : ज़्यादातर लोन राज्य सरकार की गारंटी से मिलते हैं।

Steady..
Focused..
almost there

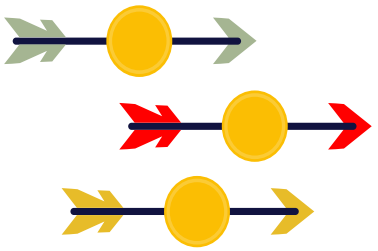

क्रेडिट इम्पेयर्ड एसेट्स – रिज़ॉल्यूशन/रिकवरी स्टेटस

कुल एनपीए ₹ 1,676.49 करोड़, शुद्ध एनपीए ₹ 88.77 करोड़ , प्रावधान कवरेज 94.70 %

कंसोर्टियम परियोजनाएं

- ₹1,095.35 करोड़
- 07 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी प्रस्ताव के तहत कंसोर्टियम

- ₹1,060.37 करोड़
- 04 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

एनसीएलटी के बाहर (कंसोर्टियम परियोजनाएं)

- ₹34.98 करोड़
- 03 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

नॉन-कंसोर्टियम परियोजनाएँ

एनसीएलटी

- ₹29.78 करोड़
- 02 खातों की संख्या
- प्रावधान किया गया – 100%

मुकदमा दायर मामले/डीआरटी

- ₹403.88 करोड़
- टॉप 10: ₹ 280.12 करोड़ (69.36%)

- 9MFY26 के दौरान 7 लंबे समय से लंबित एनपीए खाते का समाधान किया गया - ₹378.73 करोड़ और 9 एनपीए खाते तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए - ₹13.25 करोड़।
- NPA अकाउंट्स से ₹378.83 Cr की रिकवरी की गई है, जिसमें 4 सरकारी एजेंसियों से ₹343.25 Cr की रिकवरी भी शामिल है।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स (9M FY26 बनाम 9M FY25)

शुद्ध लाभ

₹ 2,053.06 करोड़.
बनाम
₹ 1,981.40 करोड़.
(3.62 % ↑)

स्वीकृतियां

₹ 1,39,151.92 करोड़.
बनाम
₹ 92,151 करोड़.
(51.00% ↑)

संवितरण

9 महीनों में अब तक का सबसे अधिक ₹41,347 करोड़ का संवितरण।

सीआरएआर

38.28%

भविष्य में ग्रोथ के लिए अच्छी तरह से कैपिटलाइज़्ड

लोन बुक

अब तक की सबसे अधिक ऋण पुस्तिका
₹ 1,55,631 करोड़
(1,18,931 ↑)
(30.86%)

प्रचालन आय

₹ 9,587.54 करोड़.
बनाम
₹ 7,466.30 करोड़.
(28.41% ↑)

संपत्ति गुणवत्ता

जीएनपीए: 1.08%
एनएनपीए: 0.06%

इंडस्ट्री में सबसे अच्छे में से एक

प्रावधान कवरेज अनुपात

94.70%

मजबूत जोखिम सुरक्षा

अब तक का सबसे ज़्यादा 9M

लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	तीसरी तिमाही		नौ माह		12 माह	
	वित्त वर्ष26 (समीक्षित)	वित्त वर्ष25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष26 (समीक्षित)	वित्त वर्ष25 (समीक्षित)	वित्त वर्ष25 (लेखापरीक्षित)	वित्त वर्ष24 (लेखापरीक्षित)
आय:						
- परिचालन से राजस्व	3,431.20	2.760.23	9,587.54	7,466.30	10,311.30	7,784.29
- अन्य कमाई	74.37	9.91	114.52	27.17	37.09	163.81
कुल आय (1)	3,505.57	2,770.14	9,702.06	7,493.47	10,348.39	7,948.10
व्यय:						
- वित्तीय लागत	2,394.57	1,762.83	6,519.88	4,888.68	6,750.11	4,963.94
- अन्य लागत	400.22	92.49	779.40	257.07	372.11	348.81
- वित्तीय साधनों की हानि	(77.71)	(16.84)	(197.65)	(268.68)	(410.50)	(208.09)
कुल व्यय (2)	2,717.08	1,838.48	7,101.63	4,877.07	6,711.72	5,104.66
कर पूर्व लाभ {3= (1-2)}	788.49	931.66	2,600.43	2,616.40	3, 636.67	2,843.44
कर व्यय (4)	75.49	196.63	547.37	635.00	927.52	726.70
कर उपरान्त शुद्ध लाभ {5 = (3-4)}	713.00	735.03	2,053.06	1,981.40	2709.15	2,116.74

महत्वपूर्ण संकेतक

विवरण	नौ माह' वित्त वर्ष2026		नौ माह' वित्त वर्ष 2025		वित्त वर्ष 2025	
	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर	ईबीआर सहित	ईबीआर को छोड़कर
लोन पोर्टफोलियो (₹ करोड़)	1,55,631	1,35,631	1,18,931	98,931	1,24,828	1,04,828
ऋण पर प्रतिफल (%)	9.10%	9.14%	9.43 %	9.56 %	9.50%	9.65%
कोष की लागत (%)	7.13%	6.87%	7.46%	7.16%	7.44%	7.15%
इनकम स्प्रेड (%)	1.97%	2.27%	1.97 %	2.41 %	2.06%	2.49%
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.88%	3.30%	3.19%	3.85 %	3.22%	3.86%

विवरण	नौ माह' वित्त वर्ष2026	नौ माह' वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2025
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	1.40	1.54	1.54
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	7.28	5.17	5.72
संपत्ति पर प्रतिफल (%) (वार्षिक)	1.90	2.45	2.44
इक्विटी पर रिटर्न (%) (वार्षिक)	14.60%	14.71	15.08
नेट वर्थ (₹ करोड़)	18,744.90	17,965.59	17,969.78
औसत नेट वर्थ (₹ करोड़)	18,357.34	17,289.95	17,292.04
₹ बुक वैल्यू ₹ 10	93.64	89.74	89.76
प्रति शेयर आय (ईपीएस-वार्षिक) ₹ में	13.67	9.90	13.53

1. लोन पर यील्ड की गणना लोन एसेट्स पर ब्याज आय (NPA मामलों के सेटलमेंट पर प्राप्त ब्याज सहित) को औसत लोन एसेट्स से विभाजित करके की जाती है।
2. फंड की कॉस्ट को फाइनेंस कॉस्ट को एवरेज टोटल उधार से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है।
3. इंटरेस्ट स्प्रेड लोन पर यील्ड और फंड की कॉस्ट के बीच का अंतर है।
4. नेट इंटरेस्ट मार्जिन की गणना औसत इंटरेस्ट कमाने वाले एसेट्स द्वारा इंटरेस्ट कमाने वाले एसेट्स पर नेट इंटरेस्ट इनकम से की जाती है
5. इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो की गणना इंटरेस्ट और टैक्स से पहले की कमाई को फाइनेंस कॉस्ट से भाग देकर की जाती है।
6. टोटल डेट/नेट वर्थ (टोटल डेट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग दिखाता है) को डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है ।
7. इक्विटी पर रिटर्न की गणना उस अवधि के टैक्स के बाद के लाभ को उस अवधि के अंत में शेयरधारकों के फंड से विभाजित करके की जाती है, जिसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
8. एवरेज एसेट्स पर रिटर्न (टैक्स के बाद) की गणना उस समय के PAT को एवरेज टोटल एसेट्स से भाग देकर की जाती है।

RE
PURPOSING
EFFORTS

1. अर्बन इन्वेस्ट विंडो का शुभारंभ

- **बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास में यूएलबी के लिए <u>वन-स्टॉप एंड-टू-एंड सपोर्ट</u>** प्लेटफॉर्म
- बदलाव लाने वाली पहल - **अगले 5 सालों** में **<u>शहरी निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य</u>**
- **20 क्षेत्रीय कार्यालयों** के अखिल भारतीय नेटवर्क **<u>का पुनर्निर्माण करना</u>**, ताकि वे **स्टेट अर्बन इन्वेस्ट विंडो के रूप में कार्य कर सकें।**
- **राज्य सरकार और ULBs** के साथ मिलकर काम करना
- टेक्निकल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के लिए प्रोजेक्ट्स की पहचान, कैपिटल जुटाने से लेकर प्रोजेक्ट को लागू करने तक
- **<u>बैंकेबल</u>**, **इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार** शहरी प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन बनाएं
- फ़ीज़िबिलिटी स्टडीज़ और फ़ाइनेंस पाने में मदद - **[illegible] एजेंसियां (वर्ल्ड बैंक, KfW, ADB),** FIs, म्युनिसिपल बान्ड, FDIs,

https://www.hudco.org.in/writereaddata/National-Urban-Conclave.mp4

2. क्रेडिट एन्हास्मेंट इनिशिएटिव: अमृत 2.0

- छोटे ULBs (आबादी <1 लाख) में फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
- **हडको को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने** ₹300 करोड़ के कॉर्पस के लिए **क्रेडिट गारंटी फंड मैनेजर** के तौर पर अधिसूचित किया
- राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की पहचान करने और उन्हें लागू करने में मदद देना

3. PPP प्रोजेक्ट फाइनेंस डिवीजन का शुभारंभ

- **उद्देश्य**: बैंकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने में प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना
- **PPP प्रोजेक्ट्स** के लिए लोन देने का प्रोसेस शुरू किया गया |
- NIP 2.0 को सप्लीमेंट करते हुए - ₹17 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट का टारगेट|
- बोर्ड ने इन सेक्टर्स में फंडिंग के लिए गाइडलाइंस को मंज़ूरी दी:

रियल एस्टेट

सड़कें

समुद्री बंदरगाह

एयरपोर्ट

ऊर्जा

4. शहरी गतिशीलता

- देश भर में मेट्रो समेत अर्बन मोबिलिटी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए **पूल ऑफ़ फंड (USD 1 Bn)।**
- पूल - बैंकों सहित **विदेशी और घरेलू सोर्स का मिक्स ।**
- **उद्देश्य** : हडको की इंट्रीन्सिक स्ट्रेंग्थ का फ़ायदा उठाना और **मार्केट में प्रतिस्पर्धी दरों पर लोन देना।**

5. ब्रिज लोन

- **उद्देश्य -** भारत सरकार की योजनाओं/ कार्यक्रमों में राज्यों की सुयोग योगदान की उपलब्धता को समय पर सुनिश्चित करना

6. तकनीकी सहायता योजना

- प्रोजेक्ट बनाने, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट, R&D आदि के लिए ग्रांट।

सेक्टर आउटलुक और अवसर

2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और विकसित भारत @ 2047

(डेवलप्ड इंडिया @ 2047)

अगले पांच सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 1.6 गुना बढ़ने की उम्मीद

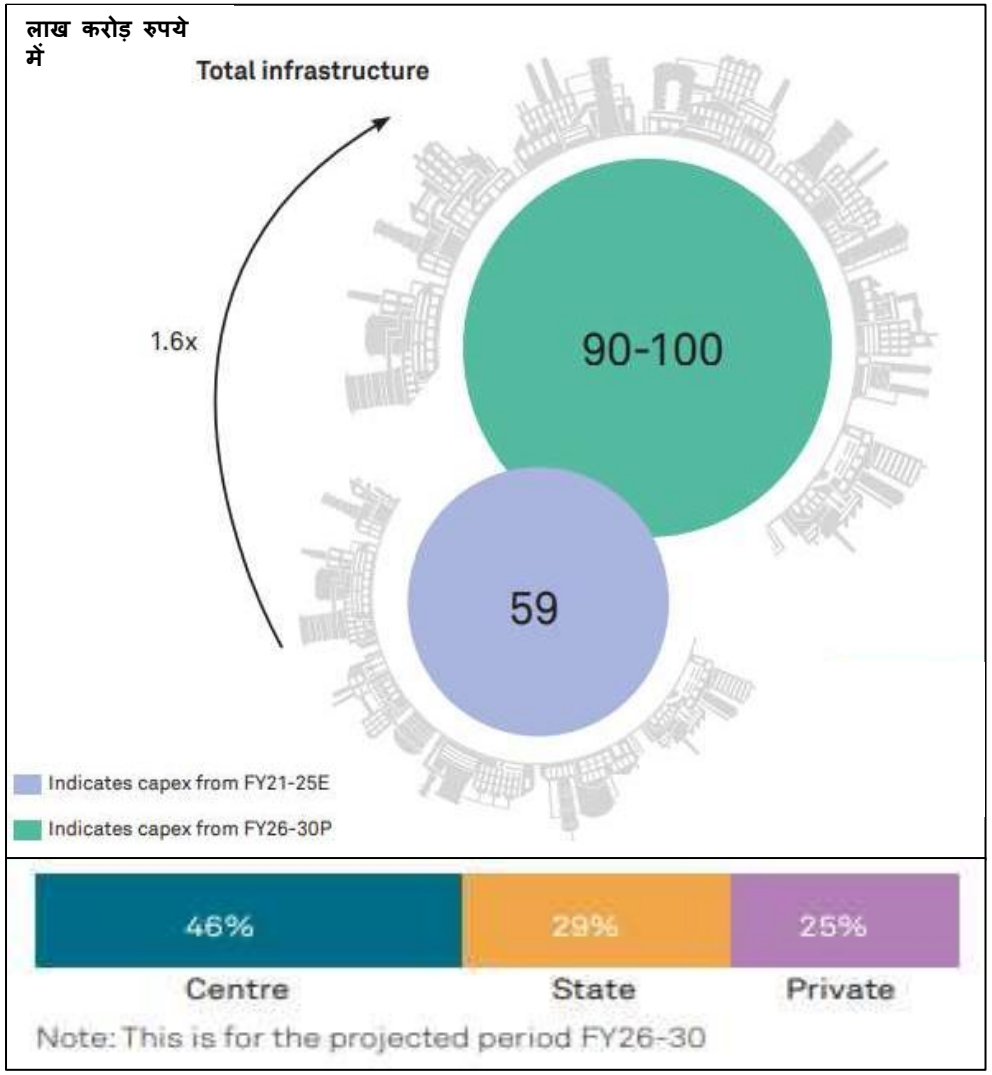

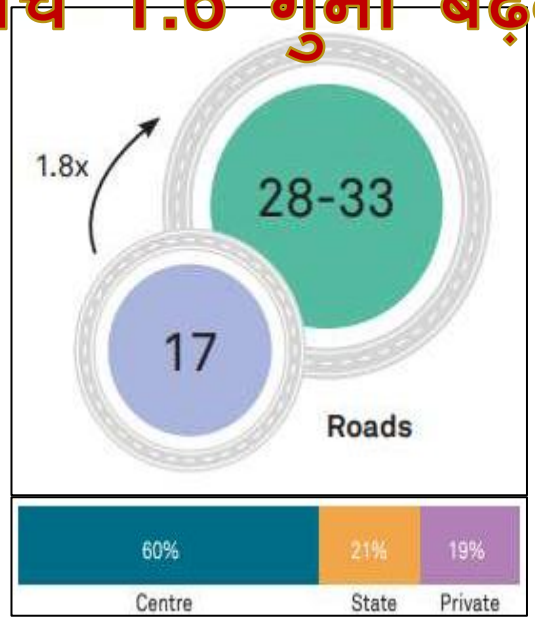

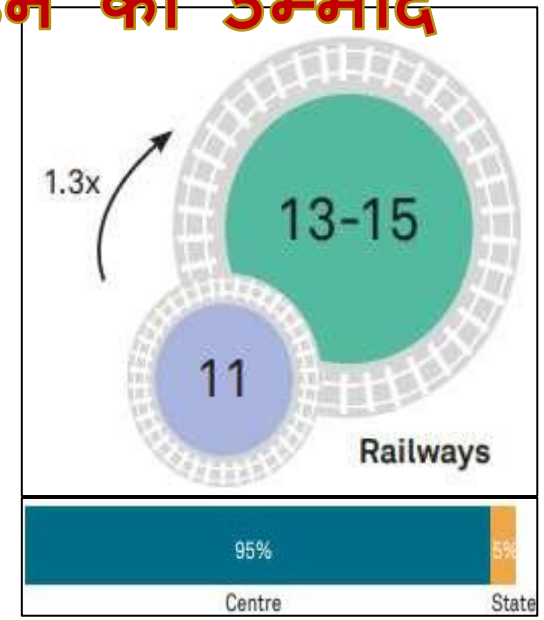

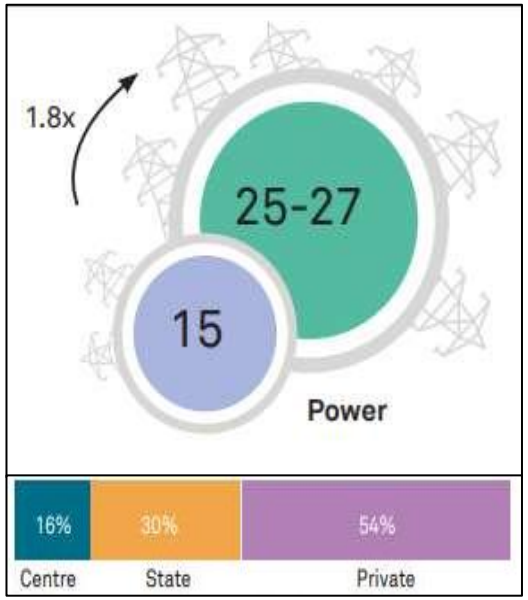

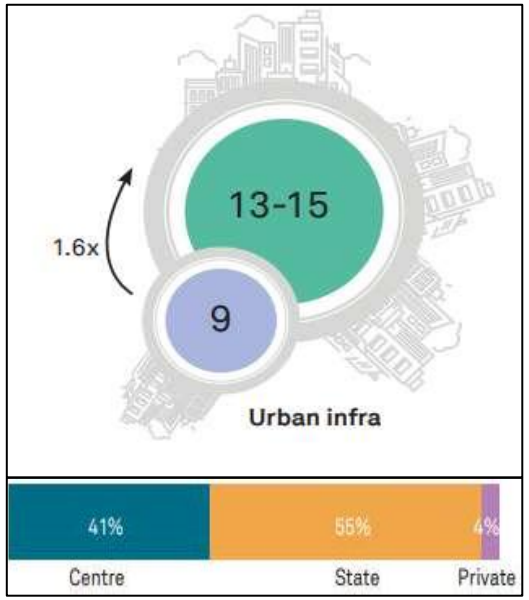

स्रोत: CRISIL इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025

हडको की उभरती भूमिका – विकास के लिए प्रेरक

2030 तक $10 ट्रिलियन की इकॉनमी और 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ने के सरकार के विज़न से **इंफ्रा** डेवलपमेंट **के लिए फंडिंग की भारी मांग पैदा होने वाली है,** जिसमें ये पहल शामिल हैं:

भूमि अधिग्रहण, एकीकृत टाउनशिप और औद्योगिक कॉरिडोर

गतिशीलता – मेट्रो, एक्सप्रेसवे आदि।

PMAY 2.0 में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हाउसिंग शामिल है

स्मार्ट सिटीज, अमृत, जेजेएम, एसबीएम 2.0

स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा संक्रमण

बंदरगाह वित्तपोषण (बंदरगाह और हवाई अड्डा)

- इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पूरे लैंडस्केप के लिए लोन देकर भारत सरकार के विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
- प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना शुरू किया।

“विकसित भारत के लिए विकसित प्रदेश

₹1.5 लाख करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए MMRDA के साथ समझौता ज्ञापन

₹1 लाख करोड़ की फाइनेंशियल मदद के लिए एमपी सरकार के साथ MoU

राजस्थान के साथ हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ₹ 1 लाख करोड़ का MoU

भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ के MoU
पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट

छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ₹ 1 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

₹11,300 करोड़ के वित्तीय सहायता के लिए NMRDA के साथ समझौता ज्ञापन

बिल्डिंग द बैकबोन ऑफ़ ए विकसित भारत

ओप्टिमम कॉस्ट रिसोर्स पाने के लिए ECB की तीसरी ट्रांच

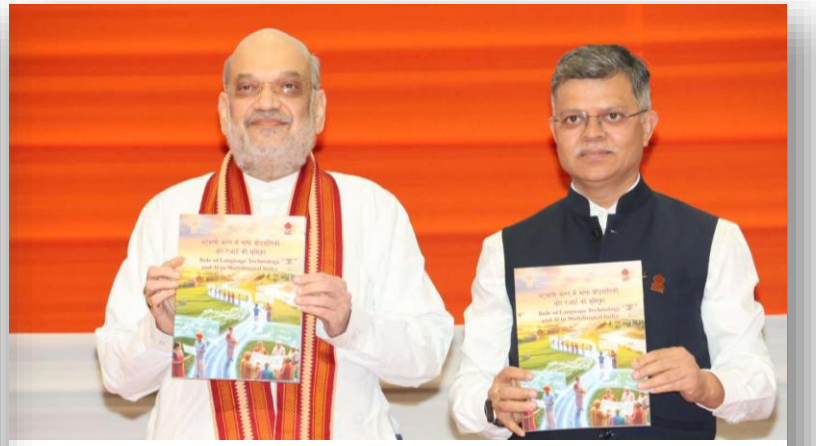

गृह मंत्रालय और हडको द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित हिंदी पुस्तक का विमोचन

हडको 54EC कैपिटल गेन टैक्स एक्जेम्प्शन बॉन्ड लॉन्च

हडको की प्रॉपर्टीज़ को मिलकर डेवलप करने के लिए NBCC के साथ MoU साइन किया गया

NAREDCO इवेंट के दौरान रियल एस्टेट में प्राइवेट सेक्टर फंडिंग की शुरुआत

अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रभावी विकास के लिए NIUA के साथ समझौता ज्ञापन

प्रेरक सम्मान

- 17वां बीएमएल मुंजाल बिजनेस एक्सीलेंस अवॉर्ड
- ETNOW इंफ्रा फोकस अवार्ड्स 2024: इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर (हाउसिंग)
- गवर्नेंस नाउ 11वां PSU अवार्ड्स: PSU और CSR लीडरशिप
- WCDM अवार्ड 2024: 'गुड प्रक्टिसेज इं रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन '
- पृथ्वी अवॉर्ड 2024: सस्टेनेबल डेवलपमेंट और CSR पहल

- एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन के लिए PSE एक्सीलेंस अवार्ड 2025
- परामर्श परियोजना के लिए गृह पुरस्कार
- एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स: साउथ एशिया में बेस्ट सस्टेनेबिलिटी लोन (ESG)
- राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024-25
- 5वां PSU ट्रांसफॉर्मेशन अवॉर्ड – फास्टेस्ट ग्रोइंग PSU

धन्यवाद

विकसित भारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तपोषण

मुख्यालय:
हडको भवन, कोर-7-ए,
इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

www.hudco.org.in @hudco @hudcolimited @hudco-limited @hudcoltd